

**सार्वजनिक रिकॉर्ड । खुली बैठकें । स्थानीय संस्थाओं को राजकीय प्रतिपूर्ति । विधायी संवैधानिक संशोधन ।**

- स्थानीय सरकारी संस्थाओं, जिनमें शहर, काउंटी, और स्कूल डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, के लिए स्थानीय सरकारी निकायों की बैठकों और सरकारी अधिकारियों के रिकॉर्ड की सार्वजनिक सुलभता प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट राज्य कानूनों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- इस आवश्यकता को खत्म करता है कि राज्य इन निर्दिष्ट कानूनों का अनुपालन करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को प्रतिपूर्ति करे।

**राज्य और स्थानीय सरकार पर पड़ने वाले शुद्ध राजकोषीय प्रभाव का विधायी विश्लेषक के अनुमान का सारांश:**

- स्थानीय सरकारों को राज्य द्वारा किये जाने वाले भुगतानों में वार्षिक रूप से दसियों मिलियन डॉलर की कमी की।
- स्थानीय सरकारों पर जनसामान्य को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लगायी गयी सम्भावी अतिरिक्त राजकीय आवश्यकताओं से स्थानीय सरकारों की लागतों में वार्षिक रूप से दसियों मिलियन डॉलर की सम्भावित वृद्धि हुई।

**SCA 3 (प्रस्ताव 42) पर विधानमंडल द्वारा डाले गये अन्तिम वोट  
(संकल्प 123, 2013 के कानून)**

सीनेट:	हाँ 37	नहीं 0
विधानसभा:	हाँ 78	नहीं 0

**विधायी विश्लेषक के द्वारा किया गया विश्लेषण**

**पृष्ठभूमि**

*California* में हजारों स्थानीय सरकारें हैं। *California* वासी हजारों स्थानीय सरकारों—काउंटियों, शहरों, स्कूल और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स, और विशेष डिस्ट्रिक्ट्स (जैसे कि फायर डिस्ट्रिक्ट्स, बाढ़ नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट्स, और वाटर डिस्ट्रिक्ट्स) से सेवायें प्राप्त करते हैं। हर स्थानीय सरकार का एक स्थानीय प्रशासी निकाय है (जैसे कि सिटी काउंसिल या काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स) जो अपने कार्यक्रमों, सेवाओं, और परिचालनों के बारे में निर्णय लेता है।

**स्थानीय सरकारी जानकारी की सार्वजनिक सुलभता** । राज्य के संविधान के अनुसार आवश्यक है कि प्रशासी निकायों की बैठकें और सरकारी अधिकारियों व एजेंसियों के लेखन रिकॉर्ड सार्वजनिक जाँच के लिए खुले हों। दो राजकीय कानून स्थानीय सरकारों के द्वारा स्थानीय सरकारी जानकारी और बैठकों की सार्वजनिक सुलभता प्रदान करने हेतु पालन किये जाने वाले नियमों की स्थापना करते हैं।

- **California सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम** । यह कानून प्रत्येक व्यक्ति को राज्य और स्थानीय सरकार के दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उनकी प्रतियां प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके अनुसार राजकीय संस्थाओं और स्थानीय सरकारों के लिए दस्तावेजों की सार्वजनिक सुलभता हेतु लिखित मार्गनिर्देश स्थापित करना और इन मार्गनिर्देशों को अपने कार्यालयों पर लगाना आवश्यक है।
- **Ralph M. Brown ऐक्ट** । यह कानून स्थानीय सरकारों के प्रशासी निकायों की बैठकों को नियंत्रित करता है। इसके अनुसार स्थानीय प्रशासी निकायों को एजेंडे के मद्दों का सार्वजनिक नोटिस प्रदान करना और खुले फोरम में बैठकें आयोजित करना आवश्यक है।

**सार्वजनिक रिपोर्ट्स के लिए राजकीय भुगतान और Brown ऐक्ट सम्बन्धी लागतें।** इन वर्षों में, विधानमंडल ने सार्वजनिक रिपोर्ट्स अधिनियम और Brown ऐक्ट को समय समय पर संशोधित किया है। इनमें से कुछ बदलावों ने स्थानीय सरकार की जिम्मेदारियां और लागतें बढ़ा दी हैं। राज्य को सामान्यतया उस दशा में स्थानीय सरकारों को उनकी लागतों का भुगतान करना चाहिये जब उनकी जिम्मेदारियों में वृद्धि करे—यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसको राजकीय अधिकारी ऐसे प्रस्तावों की समीक्षा करते समय ध्यान में रखते हैं जो स्थानीय सरकार की लागतों में वृद्धि करते हैं। वर्तमान कानून के तहत, स्थानीय सरकारों को सार्वजनिक रिपोर्ट्स अधिनियम के कुछ भागों (जैसे कि रिपोर्ट्स चाहने वाले जनसामान्य के सदस्यों की सहायता करने और रिपोर्ट्स चाहने वाले व्यक्तियों को यह बताने की आवश्यकता कि रिपोर्ट्स प्रदान किये जा सकते हैं अथवा नहीं) को लागू करने के लिए उनकी लागतों का भुगतान राज्य को करना चाहिये। सार्वजनिक रिपोर्ट्स अधिनियम के लिए राज्य के द्वारा स्थानीय सरकारों को देय धनराशि अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यह राशि वार्षिक रूप से दसियों मिलियन डॉलर होगी। इसके अलावा, राज्य ने पूर्व में स्थानीय सरकारों को Brown ऐक्ट के कुछ भागों को लागू किये जाने के कारण आयी उनकी लागतों के लिए भुगतान किया है। हालाँकि, California के मतदाताओं ने स्थानीय सरकारों को Brown ऐक्ट की इन लागतों हेतु भुगतान करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को खत्म करने हेतु 2012 में राज्य के संविधान में संशोधन किया था।

## प्रस्ताव

यह विधेयक:

- राज्य के संविधान में इस आवश्यकता को जोड़ता है कि स्थानीय सरकारें सार्वजनिक रिपोर्ट्स अधिनियम और Brown ऐक्ट का पालन करें।
- स्थानीय सरकारों को इन कानूनों से सम्बन्धित उनकी लागतों के

लिए भुगतान करने की राज्य की जिम्मेदारी को खत्म करता है। (जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, Brown ऐक्ट सम्बन्धी स्थानीय लागतों के लिए भुगतान करने की राज्य की जिम्मेदारी को 2012 में खत्म कर दिया गया था।)

यह विधेयक इन कानूनों की वर्तमान आवश्यकताओं, और साथ ही सरकारी जानकारी या बैठकों की सार्वजनिक सुलभता में सुधार लाने के लिए इनमें से किसी भी कानून में भविष्य में किये जाने वाले कोई भी बदलावों के लिए लागू होता है।

## राजकोषीय प्रभाव

**राज्य की लागतों और स्थानीय राजस्व की राशियों पर प्रभाव।** सार्वजनिक रिपोर्ट्स अधिनियम का पालन करने के लिए स्थानीय सरकारों की लागतों हेतु भुगतान करने की राज्य की जिम्मेदारी को खत्म करके, इस विधेयक के परिणामस्वरूप राज्य को बचत होगी और स्थानीय सरकारों के राजस्व में तुलनीय गिरावट आयेगी। यह प्रभाव सम्भवतया वार्षिक रूप से दसियों मिलियन डॉलर का होगा।

**स्थानीय लागतों पर सम्भावी प्रभाव।** यह विधेयक राज्य के अधिकारियों के भावी व्यवहार को भी बदल सकता है। क्योंकि प्रस्ताव 42 के तहत, राज्य सार्वजनिक रिपोर्ट्स अधिनियम में बदलाव कर सकता है और उसे स्थानीय सरकारों को उनकी लागतों के लिए भुगतान नहीं करना होगा। इस प्रकार, राज्य के अधिकारी इस कानून में उससे कहीं अधिक बदलाव कर सकते हैं जितने वे अन्यथा कर पाते। इस मामले में, स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त लागतें उठानी पड़ सकती हैं—सम्भावित रूप से भविष्य में सालाना दसियों मिलियन डॉलर।

इस प्रस्ताव के लिए वित्तीय योगदानों के बारे में विवरण के लिए <http://cal-access.sos.ca.gov> देखें।